Working group on investment promotion strategies

3952. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have set up a working group to go into various issues on 'rationalisation and harmonisation' of investment strategies;

(b) whether the Group will be represented by various States and concerned institutions also;

(c) if so, what will be the main objective of the working group; and

(d) what are the main issues that will be considered by the Group; and

(e) by when the working group is likely to submit its recommendations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (e) The Government has constituted a Working Group under the Chairmanship of Additional Secretary, Department of Industrial Development and consisting of Industries Secretaries of select states on 17th February, 1994 to suggest strategies relating to investment promotion measures keeping in view the specific requirements of State Governments. The Working Group will examine :

(i) options of working out modalities which would ensure a more cost effective utilisation of the limited resources available with the States and Centre, simultaneously taking care of the legitimate aspirations of the relatively backward States; and

(ii) Issues relating to rationalisation and harmonisation of policies and incentives for promotion of industries keeping in view the specific requirement of State Governments.

The Working Group is expected to submit its report within three months.

गुजरात में स्थापित लघु उद्योग

3953. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय जिलेवार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों में मासिक और दैनिक वेतन पर कितने-कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) उनके उत्पादों के विपणन हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या उनमें से कुछ उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-1992 को लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) के क्षेत्राधिकार में आने वाली 94,879 लघु इकाइयों को स्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था । इन इकाइयों के जिलेवार ब्यौरे विवरण I में दिये गये हैं ।

(ख) इन उद्योगों में मासिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1989—91 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की गई लघु औद्योगिक इकाइयों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार, उपलब्ध आंकड़े विवरण-II में दिये गये हैं जिसका आधार वर्ष 1987-88 है ।

(ग) विपणन मुख्यतया एक उद्यमिता कार्य है । तथापि, लघु उद्योग के कमजोर आधार पर विचार करते हुए 409 मदों को केवल सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के तहत खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर पंजीकरण योजना के तहत निम्नलिखित विशेष सुविधाएं दी गयीं हैं :—

(1) निःशुल्क टेंडर सेट जारी करना ।

(2) बयाना राशि के भुगतान की छूट ।

(3) जिस आर्थिक सीमा तक उतनी इकाई पंजीकृत है उतनी राशि तक सिक्युरिटी डिपाजिट की छूट ।

(4) बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कोटेशनों की तुलना में गुणदोष के आधार पर 15% तक मूल्य वरीयता ।

गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारें अपने-अपने नीतिगत उपायों के अनुसार राज्य खरीद कार्यक्रम के तहत उनके उत्पादों को बेचने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों की सहायता करते हैं ।

(घ) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात में मार्च, 1992 के अंत तक 6581 रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां थी ।

(ङ) राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति और राज्य स्तरीय पुर्नस्थापना समिति के माध्यम से जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के

लिए नियमित आधार पर उपाय किये जा रहे हैं। जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना में बैंकों द्वारा भी नियमित आधार पर मदद की जा रही है। राष्ट्रीय ईक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक की दीर्घावधि ईक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। लघु औद्योगिक इकाइयों में व्याप्त रुग्णता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यवाही करने हेतु मुख्य-मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठ स्थापित करें और तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञों की सेवा मुहैया करायें।

विवरण I

गुजरात में 31-12-92 को पंजीकृत सीडी इकाइयों की जिलेवार समेकित संख्या का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	31-12-92 को इकाइयों की समेकित संख्या
1.	अहमदाबाद	25565
2.	गांधीनगर	861
3.	नाडियाड	4378
4.	बडोदरा	6516
5.	भरोच	3381
6.	सूरत	8380
7.	वलसाद	5419
8.	वपी	
9.	सुरेन्द्रनगर	2823
10.	राजकोट	12036
11.	जामनगर	5228
12.	भुज	1313
13.	भावनगर	4887
14.	अमरेली	1512
15.	जूनागढ़	2500
16.	मेहसाना	4115
17.	साबरकान्था	2240
18.	बनासकान्था	1468
19.	पंचमहल	2247
20.	डांग्स	10
	योग :	94879

विवरण II

कर्मचारियों का जिलेवार वर्गीकरण--1987-88

क्रम सं०	जिला	कर्मचारियों का वर्गीकरण (संख्या)		कुल कर्मचारी	स्वयं नियोजित
		सीधे भर्ती/ नियमित	दिहाड़ी/ ठेके पर		
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	55396	9367	64763	13427
2.	अमरपाली	783	516	1299	706
3.	बनासकान्था	2977	2	2979	793
4.	भरोच	8019	951	8970	1490
5.	भावनगर	10024	9212	19236	3337
6.	डांग्स	7	..	7	2
7.	गांधीनगर	1551	1236	2787	329
8.	जामनगर	7519	3371	10890	2622
9.	जूनागढ़	4887	2226	7113	1519
10.	खेड़ा	11734	1707	13441	3108

1	2	3	4	5	6
11.	कच्छ	3342	670	4012	620
12.	मेहसाना	8775	4078	12853	1873
13.	पंचमहल	5727	2160	7887	1012
14.	राजकोट	20753	14482	35235	7949
15.	साबरकान्था	4419	84	4503	1405
16.	सूरत	14118	3228	17346	5129
17.	सुरेन्द्रनगर	8344	777	9121	1714
18.	बडोदरा	21219	3920	25139	3982
19.	बलसाढ	23744	5630	29374	3619
	योग :	213338	62617	276955	54636

स्रोत : राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत लघु उद्योगों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना ।

Setting up of SSIs by MNCs

3954. SHRI S. AUSTIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to allow entry of multinational companies into small scale industry sector;

(b) if so, the details of the small scale industries which have been opened for multinationals;

(c) whether Government have received applications from the multinational companies in this regard ; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) In respect of items reserved for exclusive manufacture in the small scale sector, no medium or large scale units including multinationals are allowed to enter into these areas except with 75% export obligation (in the case of export oriented readymade garment units it is 50% with investment limit of Rs. 3 crores).

Provisions pertaining to 75% export obligation and permitting not more than 24% equity participation in SSI sector by other industrial undertakings both domestic and foreign are meant to protect the interest of the small scale sector.

(c) and (d) As per the latest available information, a statement giving details of the multinational companies to which licences have been issued for the items reserved for the small scale industries with 75% export obligation after the introduction of the new industrial policy is given in the Annexure [*See* Appendix 170, Annexure 76].

Industrial sickness due to labour militancy

3955. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that labour militancy has been one of the causes responsible for turning industrial sick units, particularly in the eastern part of the country ;

(b) the details of industries that were rendered sick basically due to industrial unrest in the country in general and in the eastern part of the country in particular ; and

(c) the steps contemplated by Government to tackle the ever-burgeoning unemployment problem in these States where large unemployed youth alongwith those rendered unemployed or to be rendered unemployed have been chasing very little employment opportunities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) A number of causes, both internal and external often operating in combination, have been responsible for industrial sickness. Some of the principal causes are faulty planning, management deficiencies, inefficient financial control, diversion of resources, inadequate attention to Research and Development, obsolescence of technology and machinery, poor industrial relations, inadequacy of demand, shortage of raw materials and other inputs, infrastructural constraints, etc. No specific analysis to isolate the impact of any one factor, such as labour militancy, has been attempted.

(b) The Reserve Bank of India compiles data regarding number of sick industrial units assisted by banks in the